

रजिस्टर्ड नं० एल० 33-एस० एम० 13-14/98.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 30 जुलाई, 1998/8 श्रावण, 1920

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171004, 30 जुलाई, 1998

संख्या 1-19/98-वि०स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1997 के नियम 140 के अन्तर्गत मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन

2770-राजपत्र/98-30-7-98—1,295.

(2855)

मूल्य : 1 रुपया।

विधेयक, 1998 (1998 का विधेयक संख्यांक 13) जो दिनांक 30 जुलाई, 1998 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

अजय भण्डारी,
सचिव

1998 का विधेयक संख्याक 13

मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 1998

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 (1971 का 3) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के उनवासर्वे वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संक्षिप्त नाम। संशोधन अधिनियम, 1998 है।

2. मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 में, “दो हजार पांच सौ” शब्दों के स्थान पर, “चार हजार” शब्द रखे जाएंगे। धारा 3 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3-क में,—

धारा 3-क का संशोधन।

(i) खण्ड (क) में, “दो हजार आठ सौ पच्चीस” शब्दों के स्थान पर, “पांच हजार” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खण्ड (ख) में, “दो हजार” शब्दों के स्थान पर, “तीन हजार पांच सौ” शब्द रखे जाएंगे ; और

(iii) खण्ड (ग) में, “एक हजार सत्त सौ” शब्दों के स्थान पर, “तीन हजार” शब्द रखे जाएंगे।

4. मूल अधिनियम की धारा 5-क में, “साठ हजार” शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, “अस्सी हजार” शब्द रखे जाएंगे। धारा 5-क का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक में, “तीन हजार” शब्दों के स्थान पर, “चार हजार” शब्द रखे जाएंगे। धारा 8 का संशोधन।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

निर्वाह व्यय और उन खर्चों, जो कि माननीय मन्त्री को जन प्रतिनिधि के रूप में जन-जीवन की विभिन्न मांगों के कारण उपगत करने पड़ते हैं, में तेज वृद्धि के कारण प्रत्येक मन्त्री को संदेय वेतन 2500/- रुपए से 4000/- रुपए और मुख्य मन्त्री को 2825/- रुपए से 5000/- रुपए, अन्य मन्त्रियों को 2000/- रुपए से 3500/- रुपए तक और राज्य मन्त्री को 1700/- रुपए से 3000/- रुपए तक सत्कार भत्ता बढ़ाना संदेय और उनके निर्वाचन क्षेत्र के भीतर किसी स्थान या उनके स्थायी निवास स्थान पर संस्थापित टेलीफोन के बारे में स्थानीय और बाह्य कालों पर व्यय की प्रतिपूर्ति को तीन हजार रुपए से चार हजार रुपए प्रति मास तक बढ़ाना और रेलवे या वायु मार्ग द्वारा निःशुल्क यात्रा सुविधा की अधिकतम सीमा किसी वित्तीय वर्ष में साठ हजार किलोमीटर से अस्सी हजार किलोमीटर तक बढ़ाना आवश्यक समझा गया है। अतः मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री।

शिमला:

..... जुलाई, 1998

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक क खण्ड 2 से 5 के अधिनियमित किए जाने पर राजकोष से प्रति वर्ष 9 लाख रुपए का अतिरिक्त आवर्ती व्यय करना पड़ेगा। क्योंकि प्रस्तावित संशोधन भावी प्रभाव का है, इसलिए कोई अनावर्ती व्यय नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[सामान्य प्रशासन विभाग, फाईल संख्या जी० ए० डी० सी(पी० ए०) 4-22/94-II]

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 1998 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती है।

मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 1998

मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 (1971 का 3) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
सचिव (विधि)।

शिमला :

..... जुलाई, 1998

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 13 of 1998.

THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH) AMENDMENT BILL, 1998

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 1971 (Act No. 3 of 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-ninth Year of the Republic of India, as follows :—

1. This Act may be called the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Amendment Act, 1998. Short title.

2. In section 3 of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 1971 (hereinafter called the principal Act), for the words “two thousand and five hundred”, the words “four thousand” shall be substituted. Amendment of section 3.

3. In section 3-A of the principal Act, —

(i) in clause (a), for the words “two thousand, eight hundred and twenty five”, the words “five thousand” shall be substituted;

(ii) in clause (b), for the words “two thousand”, the words “three thousand and five hundred” shall be substituted; and

(iii) in clause (c), for the words “one thousand and seven hundred”, the words “three thousand” shall be substituted. Amendment of section 3-A.

4. In section 5-A of the principal Act, for the words “sixty thousand”, wherever these occur, the words “eighty thousand” shall be substituted. Amendment of section 5-A.

5. In section 8 of the principal Act, in sub-section (1), in the first proviso, for the words “three thousand”, the words “four thousand” shall be substituted. Amendment of section 8.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Due to sharp increase in the cost of living and the considerable expenses which an Hon'ble Minister, as a public representative, has to incur on account of various demands of the public life, it has been considered necessary to increase salary payable to each Minister from Rs. 2500/- to Rs. 4000/- and sumptuary allowances payable to Chief Minister from Rs. 2825/- to Rs. 5000/-, to other Ministers from Rs. 2000/- to Rs. 3500/- and to State Minister from Rs. 1700/- to Rs. 3000/- and to increase the re-imbursement of telephone charges from Rs. 3000/- to Rs. 4000/- per month to meet the expenses of local and outside calls in respect of telephone installed at any place within his constituency or at his permanent place of residence and to raise the maximum limit of free transit by railway or by air facility from sixty thousand kilometres to eighty thousand kilometres in a financial year. This has necessitated the amendments in the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 1971.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

SHIMLA :
The.....July, 1998.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clauses 2 to 5 of the Bill, when enacted, will entail additional recurring expenditure out of the State Exchequer to the tune of Rs. 9 lakhs per annum. As the proposed amendment is prospective in effect there will be no non-recurring expenditure.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-NIL-

**RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF
THE CONSTITUTION OF INDIA**

(GAD File No. GAD-C(PA)4-22/94-II)

The Governor of Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of the salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Amendment Bill, 1998, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the State Legislative Assembly.

**THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH)
AMENDMENT BILL, 1998**

A

BILL

further to amend the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 1971 (Act No. 3 of 1971).

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

SURINDER SINGH THAKUR,
Secretary (Law).

Shimla :
The....July, 1998.